F N0. T-74074/10/2019-WSE DTE/124

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Water System Engineering Directorate

दिनांक: 20.03.2020

विषय - समाचार पत्रों की कटिंग का प्रस्तुतिकरण।

जल संसाधन विकास और संबद्ध विषयों से संबंधित समाचार पत्रों की कटिंग को केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के अवलोकन के लिए संलग्न किया गया है। इन समाचारों की कटिंग की सॉफ्ट कॉपी केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

संलग्नक: उपरोक्त

अंजना
20.3.2020
वरिष्ठ कलाकार
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय

सहायक निदेशक, (ज. प्र. आ.) निदे॰ संदीप 20/03/2020

उप निदेशक, (ज. प्र. आ.) निदे॰ विकास 20/3/2020

निदेशक, (ज. प्र. आ.) निदे॰ 20-03-2020

सेवा में,

अध्यक्ष, के. ज. आ., नई दिल्ली

जानकारी हेतु – सभी संबंधित केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट www.cwc.gov.in पर देखें।

News item/letter/article/editorial published on 20.03.2020 in the following newspaper

stan Times (New Delhi)	☐ Deccan Herald (Bengaluru)	☐ हिंदुस्तान (नई दिल्ली)	☐
Statesman (New Delhi)	☐ Deccan Cronicle	☐ नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)	☐
Times of India (New Delhi)	☑ The Economic Times (New Delhi)	☐ पंजाब केसरी (दिल्ली)	☐
he Indian Express (New Delhi)	☐ Business Standard(New Delhi)	☐ राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)	☐
The Hindu (Delhi)	☐ The Tribune (Gurugram)	☑ दैनिक जागरण (नई दिल्ली)	☐
Pioneer (Delhi)	☐ Financial Express	☐ जनसत्ता (दिल्ली)	☐
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)	☐ दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)	☐ अमर उजाला (नई दिल्ली)	☐

and documented at WSE Dte, CWC.

Mercury touches 30°C for first time this year

TIMES NEWS NETWORK T-20

New Delhi: The mercury breached the 30-degree mark for the first time this season on Thursday and is likely to touch 31°C by Friday, forecasts by India Meteorological Department (IMD) show.

Delhi's Safdarjung station recorded a maximum temperature of 30.7 degrees Celsius and a minimum of 16 degrees on Thursday.

IMD has forecast drizzle on Friday evening and a spell of light rain on Saturday. "After recently receiving hail and more than normal rain, temperatures had fallen to around 24°C. It has now returned to the normal benchmark," said Kuldeep Srivastava, scientist at IMD and the head of Regional Weather Forecasting Centre in the city.

The city's air quality remained in the 'moderate' range on Thursday, with the air quality index (AQI) slightly increasing from 151 on Wednesday to 186.

THE TRIBUNE - 20.03.2020

Rain, snow likely for 6 days: MeT

T-20

TRIBUNE NEWS SERVICE

SHIMLA, MARCH 19

The hills and valleys of Himachal are unlikely to get respite from freak weather conditions. The local MeT office has predicted another wet spell in middle and higher hills from Friday. The MeT office also warned of thunderstorm accompanied by lighting at isolated places in lower and middle hills on March 21.

Rains and snow are likely at isolated places in middle and higher hills for six days from Friday onward as a cyclonic circulation lies over southwest Rajasthan and its neighbourhood and a fresh Western Disturbance is likely to affect the western Himalayan region from the night of March 23.

News item/letter/article/editorial published on 20.03.2020 in the following newspaper

Hindustan Times (New Delhi)	☐	Deccan Herald (Bengaluru)	☐
The Statesman (New Delhi)	☐	Deccan Cronicle	☐
The Times of India (New Delhi)	☐	The Economic Times (New Delhi)	☐
The Indian Express (New Delhi)	☐	Business Standard(New Delhi)	☐
The Hindu (Delhi)	☐	The Tribune (Gurugram)	☐
Pioneer (Delhi)	☐	Financial Express	☐
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)	☐	दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)	☐

हिंदुस्तान (नई दिल्ली)	☐		
नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)	☐		
पंजाब केसरी (दिल्ली)	☐		
राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)	☐		
दैनिक जागरण (नई दिल्ली)	☐		
जनसत्ता (दिल्ली)	☐		
अमर उजाला (नई दिल्ली)	☐		

and documented at WSE Dte, CWC.

Telegraph, Kolkata

PAPERBACK PICKINGS

When tides turn

THINKING ABOUT WATER IN UNCERTAIN TIMES: STATE, PEOPLE AND CONFLICTS (Aakar, Rs 295) *by Sailen Routray and N. Shantha Mohan* is a timely anthology of essays that emerged from the authors' work for the water programme at the National Institute of Advanced Studies. Climate change and human callousness have rendered water one of the most precious resources of the 21st century, with parched countries and states using it as a bargaining chip to get their way. Routray pens an insightful piece on the inherent flaws of the river-linking project, not just underlining the ways in which this would worsen socio-economic inequalities but also highlighting alternative, more modern, technology that could have greater

benefits. Success stories where the authors describe how sharing of water can usher in peace hold out hope for a future where the right to life does not become fodder for regional politics.

Although the experts discuss many technical issues, they steer clear of jargons and keep their arguments simple enough for lay readers.

News item/letter/article/editorial published on 20.03.2020 in the following newspaper

Hindustan Times (New Delhi)	☐	Deccan Herald (Bengaluru)	☐
The Statesman (New Delhi)	☐	Deccan Cronicle	☐
The Times of India (New Delhi)	☐	The Economic Times (New Delhi)	☐
The Indian Express (New Delhi)	☐	Business Standard(New Delhi)	☐
The Hindu (Delhi)	☐	The Tribune (Gurugram)	☐
Pioneer (Delhi)	☐	Financial Express	☐
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)	☐	दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)	☐

हिंदुस्तान (नई दिल्ली)	☐		☐
नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)	☐		☐
पंजाब केसरी (दिल्ली)	☐		☐
राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)	☐		☐
दैनिक जागरण (नई दिल्ली)	☐		☐
जनसत्ता (दिल्ली)	☐		☐
अमर उजाला (नई दिल्ली)	☐		☑

and documented at WSE Dte, CWC.

गंगा सफाई अभियान कहां तक पहुंचा?

जिस गंगा में स्नान को लोग पुण्य का सबब मानते थे, आज उसमें स्नान जानलेवा भयंकर बीमारियों की वजह बनता जा रहा है। 2014 के मुकाबले गंगा आज बीस गुना अधिक मैली है। गंगाजल के वैज्ञानिक परीक्षण इस तथ्य के जीते जागते सबूत हैं।

ज्ञानेन्द्र रावत

बीते दिनों दो समाचार अखबारों की सुर्खियां बने। एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान जिसमें उन्होंने गंगा आमंत्रण अभियान के सहभागियों के स्वागत समारोह में कहा था कि केंद्र सरकार के 'नमामि गंगे' अभियान से गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता सुधरी है और देश की अति महत्वपूर्ण नदियों में एक गंगा को स्वच्छ बनाने की यह परियोजना काफी सफल रही है। सरकार देश की अन्य नदियों को साफ करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऐसी ही अन्य पहल करेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आया दूसरा बयान था कि उत्तर प्रदेश में साबरमती की तर्ज पर गंगा के तटों का सौंदर्यीकरण होगा। इसमें लोगों के स्नान के लिए घाट और अन्य सुविधाओं के साथ-साथ उनके बैठने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। यह काम राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में पास प्रस्तावों के आधार पर विकास प्राधिकरणों के साथ निकायों के संयुक्त प्रयास से पूरे किए जाएंगे। ये प्रयास किसी हद तक सराहनीय हैं, लेकिन इनसे गंगा की शुद्धि का सवाल तो अनसुलझा ही रहा।

असलियत यह है कि दुनिया भर में पतितपावनी, मोक्षदायिनी, पुण्यसलिला नदी के रूप में जानी जाने वाली नदी गंगा आज अपने अस्तित्व के लिए ही जूझ रही है। जिस गंगा में स्नान को लोग पुण्य का सबब मानते थे, आज उसमें स्नान जानलेवा भयंकर बीमारियों की वजह बनता जा रहा है। 2014 के मुकाबले गंगा आज बीस गुना अधिक मैली है। यह जगजाहिर है और गंगाजल के वैज्ञानिक परीक्षण इस तथ्य के जीते जागते सबूत हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की थी। इसकी सफलता का जिम्मा केंद्र के सात मंत्रालयों को सौंपा गया। एक अलग मंत्रालय भी बनाया गया। दावा किया गया कि गंगा सफाई का परिणाम अक्तूबर 2016 से दिखने लगेगा। उसके बाद समय-समय पर गंगा सफाई के बारे में दावे-दर-दावे किए जाते रहे और गंगा सफाई की समय सीमा भी बढ़ती रही इस दौरान सम्मेलन भी हुए। उसमें बेतहाशा पैसा खर्च हुआ और योजनाए-दर-योजनाएं जरूर बनती रहीं। दावे भले कुछ भी किए जाएं गंगा दिन-ब-दिन और मैली हो रही है। गंगा का प्रदूषण अब पहले से बहुत ज्यादा हो गया है, इस बात का प्रमाण यह है कि गंगा में नील धारा और नरौरा बैराज में 30 प्रतिशत पक्षियों तथा जलीय जंतुओं की संख्या बहुत तेजी से घटी है। कन्नौज से लेकर कानपुर, इलाहाबाद, बनारस के बीच कैंसर, आंत्रशोथ आदि जानलेवा बीमारियों के रोगियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। गंगाजल में फॉस्फेट, क्रोमियम, नाइट्रेट की तादाद बढ़ती ही जा रही हैं। इसका असर खेती पर दिखने लगा है। दारा नगर गंज (बिजनौर) से नरोरा बैराज तक डॉल्फिन की संख्या जो पहले 56 थी अब घटकर 30 के आसपास रह गई है। प्रदूषण के चलते प्रवासी पक्षी भी रूठ रहे हैं और वे किनारा कर रहे हैं। अक्सर होता यह है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नदी के बीचों-बीच से सैंपल ले लिए जाते हैं। इससे किनारों की स्थिति का अंदाजा लगा लिया जाता है। यदि किनारे के सैंपल लिए जाएं, तो हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की चेतावनी के बाद भी गंदे नाले गंगा नदी में मिल रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक एवं आईयूसीएन के पूर्व प्रमुख डा. एम.एस.स्वामीनाथन का कहना है, 'इसे इतिहास की विडंबना ही समझिए कि कालांतर में गंगा आध्यात्मिक केंद्रों को महत्व देने वाली तो रही है, परंतु आधुनिक समय में इसे प्रदूषण का शिकार होना पड़ा है। वह जलधारा जो जीवन को सिंचित और पल्लवित करती रही है, अब एक विकट, रोग प्रसारी, प्रदूषित जलकोष बनकर रह गई है।'

News item/letter/article/editorial published on 20.03.2020 in the following newspaper

Hindustan Times (New Delhi)	☐	Deccan Herald (Bengaluru)	☐
The Statesman (New Delhi)	☐	Deccan Cronicle	☐
The Times of India (New Delhi)	☐	The Economic Times (New Delhi)	☐
The Indian Express (New Delhi)	☐	Business Standard(New Delhi)	☐
The Hindu (Delhi)	☐	The Tribune (Gurugram)	☐
Pioneer (Delhi)	☐	Financial Express	☐
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)	☐	दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)	☐

हिंदुस्तान (नई दिल्ली)	☐		☐
नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)	☐		☐
पंजाब केसरी (दिल्ली)	☐		☐
राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)	☐		☐
दैनिक जागरण (नई दिल्ली)	☐		☐
जनसत्ता (दिल्ली)	☐		☐
अमर उजाला (नई दिल्ली)	☑		☐

and documented at WSE Dte, CWC.

भोपाल और बेंगलुरू भारत के सबसे अच्छे जल रचना वाले शहर

एजेंसी | मुंबई

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और धुबेला (छतरपुर) सहित बेंगलुरू, गुजरात का धौलावीरा सबसे दिलचस्प शहरी प्रोजेक्ट वाले भारत के ऐसे शहर और नगर हैं, जहां बेहतर जल रचना है। ये शहर और नगर जल आपूर्ति का प्रबंधन करते हैं और संरक्षण करते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन (डब्ल्यूयूडी) की गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, विश्वस्तर पर दक्षिण अफ्रीका का केपटाउन, मोजाम्बिक का बेरा और पेरू का लीमा ऐसे अग्रणी शहर हैं, जिन्होंने जल संकट के समाधान के लिए नवाचार प्रक्रिया में रणनीतिक तत्व को योजना के रूप में अपनाया। रिपोर्ट 'सिटीज विथ द बेस्ट वाटर डिजाइंस' 22 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व जल दिवस से पहले जारी की गई है। डब्ल्यूयूडी के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के डीन शालीन शर्मा के मुताबिक साल 2025 तक दुनिया की दो तिहाई आबादी जल संकट का सामना कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि वर्ष 2050 तक भारत में 75 प्रतिशत आबादी शहरों में रहेगी।

News item/letter/article/editorial published on 20.03.2020 in the following newspaper

Hindustan Times (New Delhi)	☐	Deccan Herald (Bengaluru)	☐
The Statesman (New Delhi)	☐	Deccan Cronicle	☐
The Times of India (New Delhi)	☐	The Economic Times (New Delhi)	☐
The Indian Express (New Delhi)	☐	Business Standard(New Delhi)	☐
The Hindu (Delhi)	☐	The Tribune (Gurugram)	☐
Pioneer (Delhi)	☐	Financial Express	☐
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)	☐	दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)	☐

हिंदुस्तान (नई दिल्ली)	☐		☐
नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)	☐		☐
पंजाब केसरी (दिल्ली)	☐		☐
राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)	☑		✓
दैनिक जागरण (नई दिल्ली)	☐		☐
जनसत्ता (दिल्ली)	☐		☐
अमर उजाला (नई दिल्ली)	☐		☐

and documented at WSE Dte, CWC.

प्रदेश की 295 यूनिटों में से 185 अतिदोहित श्रेणी में

राजस्थान की 3321 बस्तीवासी पीते हैं फ्लोराइड युक्त पानी

20 RP

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. राजस्थान के फ्लोराइड वाले पानी की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है, अभी भी प्रदेश की 3321 बस्तियों में रहनेवाले लाखों लोग फ्लोराइड युक्त पानी पिने को मजबूर हैं। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। साथ ही कहा कि पानी की गुणवत्ता और उसके प्रबंधन के संबंध में किए जाने वाले सभी कार्यो की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

संसद में गुरुवार को जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सवाल के जवाब में जलशक्ति मंत्रालय की ओर से बताया गया कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है और केंद्र इसमें वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। हालांकि प्रदेश में फिलहाल कोई बस्ती आर्सेनिक संदूषित से प्रभावित नहीं है।

वर्ष 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाने की दिशा में केंद्र ने राज्यों को 3.60 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जल जीवन मिशन को शुरू किया है। इसमें केंद्र की ओर से 2.08 लाख करोड़ केंद्र की ओर से वहन किया जाएगा। इसमें जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि राजस्थान में कुल 295 यूनिटों में से 185 अति दोहन की श्रेणी में है।

कई राज्यों ने किया जल संरक्षण में बेहतरीन कार्य

गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, महाराष्ट्र में जलयुक्त शिबर, गुजरात में सुजलाम सुफलाम अभियान, तेलंगाना में मिशन ककातिया, आंध्र प्रदेश में नीरू चेट्टू, बिहार में जल जीवन हरियाली, हरियाणा में जल ही जीवन मिशन के जरिए जल संरक्षण की दिशा में बेहतरीन प्रयास किए गए है।

News item/letter/article/editorial published on 20.02.2020 in the following newspaper

Hindustan Times (New Delhi)	☐ Deccan Herald (Bengaluru)	☐ हिंदुस्तान (नई दिल्ली)	☐
The Statesman (New Delhi)	☐ Deccan Cronicle	☐ नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)	☐
The Times of India (New Delhi)	☐ The Economic Times (New Delhi)	☐ पंजाब केसरी (दिल्ली)	☐
The Indian Express (New Delhi)	☐ Business Standard(New Delhi)	☐ राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)	☐
The Hindu (Delhi)	☐ The Tribune (Gurugram)	☐ दैनिक जागरण (नई दिल्ली)	☐
Pioneer (Delhi)	☐ Financial Express	☐ जनसत्ता (दिल्ली)	☐
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)	☑ दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)	☐ अमर उजाला (नई दिल्ली)	☐

and documented at WSE Dte, CWC.

यमुना प्रोजेक्ट का एनजीटी ने किया निरीक्षण

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

प्रोजेक्ट को निर्धारित समय पर पूरा करने के डीडीए को दिए निर्देश

यमुना के सौंदर्यीकरण को लेकर चल रहे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के प्रोजेक्ट का बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की मॉनिटरिंग कमेटी ने निरीक्षण किया। कमेटी के पदाधिकारी उस जगह भी गए, जहां डीडीए करीब दर्जनभर वाटर बॉडी विकसित कर रहा है। खासबात यह है कि डीडीए का यह प्रोजेक्ट सराय कालेखां के सामने यमुना के किनारे चल रहा है। करीब 16 करोड़ की इस लागत वाले प्रोजेक्ट में लोगों के मॉर्निंग वॉक एवं साइकिलिंग के लिए ट्रैक भी बनाया जा रहा है।

यमुना नदी में प्रदूषण को समाप्त करने के लिए नदी की धारा के दोनों तरफ डीडीए की सौंदर्यीकरण की योजना चल रही है। इस योजना के तहत सराय कालेखां के सामने करीब 100 हेक्टेयर जमीन पर साइकिलिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। डीडीए की योजना है कि यमुना क्षेत्र में पानी के जमीनी स्रोत को ऊपर लाने के लिए जगह-जगह वाटर बॉडी विकसित की जाएं। एनजीटी की मॉनिटरिंग कमेटी ने पूरे प्रोजेक्ट का जायजा लिया। कमेटी ने डीडीए के अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो। मॉनिटरिंग कमेटी के निरीक्षण के दौरान डीडीए के संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे।